श्री रामेश्वर ठाकुर

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधान सभा अधिवेशन

---

03 फाल्गुन, 1931 शक **भोपाल, सोमवार, 22 फरवरी 2010**

माननीय सदस्यगण,

1. विधान सभा के इस बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

2. मेरी सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हमने अधोसंरचना विकास, कृषि को लाभ का धंधा बनाना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निवेश वृद्धि, महिला सशक्तिकरण, सुशासन तथा सशक्त कानून व्यवस्था को आधार बनाया है। व्यापक सूखे के बावजूद वर्ष 2008-09 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर बढ़कर 8.67 प्रतिशत हो गई जो मेरी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2002-03 तक यह विकास दर ऋणात्मक -0.60 प्रतिशत थी। आयोजना व्यय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। 'मंथन-2009' की अनुशंसाओं

पर कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रदेश के स्थापना दिवस पर शुरू किये गये 'आओ बनायें अपना मध्यप्रदेश' अभियान में विभिन्न दलों की भागीदारी ने प्रेरणादायी संदेश दिया। प्रदेश के विकास में जनभागीदारी का आव्हान करने के लिये मध्यप्रदेश बनाओ यात्रा 26 जनवरी से शुरू की गयी है।

3. मेरी सरकार ने अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिये वर्ष 2010-11 में 25 वृहद पुलों सहित 3316 किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन का लक्ष्य रखा है। 11 हजार 110 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को मुख्य जिला मार्ग तथा एक हजार 380 किलोमीटर सड़कों को राज्य मार्ग घोषित किया गया है। छह हजार किलोमीटर राज्यमार्ग का दो-लेन तथा सात सम्भागीय मुख्यालयों को चार-लेन से जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है। 45 जिला मुख्यालय दो-लेन से जोड़े जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जिसमें प्रदेश लगातार अव्वल बना हुआ है के अंतर्गत अगले वर्ष ग्यारह हजार किलोमीटर से अधिक सड़क बनायी जायेगी।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कें बनने से परिवहन बढ़ा है। प्रदेश में नई परिवहन नीति तैयार की गई है जिसमें

छोटे यात्री वाहनों को ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों पर रियायती दरों पर परमिट देने की व्यवस्था बनाई जा रही है।

5. वर्ष 2013 तक 5 हजार मेगावॉट से अधिक विद्युत् क्षमता वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित है। निजी कम्पनियों के द्वारा 6500 मेगावॉट की पांच विद्युत् परियोजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया है। किसानों को प्रथम 500 यूनिट प्रतिमाह तक मात्र 75 पैसे एवं इससे अधिक खपत पर 110 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देने तथा अन्य वर्गों को राहत पहुंचाने के लिये इस वर्ष लगभग 1300 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। वर्ष 2010-11 में 2072 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों एवं 2055 एम. व्ही. ए. क्षमता के अति उच्च दाब उपकेन्द्रों का निर्माण किया जायेगा। विद्युत् वितरण में सुधार के लिये फीडर विभक्तिकरण का कार्य शुरू हो चुका है। विद्युत् हानियों में कमी लाने के लिये फ्रेंचाइजी के माध्यम से वितरण व्यवस्था लागू करने के अधिकार कंपनियों को दिये गये हैं। गैर परम्परागत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये विगत पांच वर्षों में 138 मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना, 249 ग्रामों का विद्युतीकरण और 18165 बायो गैस

संयंत्रों का निर्माण किया गया। नगरीय निकायों में ऊर्जा दक्ष जल पम्पों का उपयोग भी अनिवार्य किया गया है।

6. मेरी सरकार ने सूखे से पैदा जल संकट से निपटने के लिये प्रदेश के तालाबों और अन्य परम्परागत जल स्त्रोतों के संरक्षण का अभियान चलाया। प्रदेश में 300 नल जल योजनाएं पूरी करने के साथ करीब दस हजार ग्रामीण बसाहटों और 300 शालाओं में पेयजल की व्यवस्था की गई है।

7. मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में 12 नगरों की विकास योजना तैयार की जायेगी। प्रदेश में पहली बार स्पेशल टाउनशिप नियम तैयार किये गए हैं। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं उज्जैन शहरों के लिये 3181 करोड़ रुपये लागत की 48 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। शहरी गरीबों के लिये 59 हजार से ज्यादा आवास बनाये जा रहे हैं। प्रोजेक्ट उदय के तहत लगभग 980 करोड़ रुपये लागत के कार्य प्रगति पर हैं। गृह निर्माण मण्डल द्वारा अगले वर्ष 750 करोड़ रुपये की योजनायें प्रस्तावित हैं।

8. राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पूरी तत्परता से लागू किया गया है। इसके तहत इस वर्ष लगभग 38 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार मुहैया कराया जाकर लगभग 1600 करोड़ रुपये की मजदूरी दी गई है। गांव-गांव में रोजगार के अवसर निर्मित किये गये हैं। योजना के तहत इस वर्ष 3 लाख 24 हजार निर्माण कार्य लिये गये जिनमें से एक लाख 43 हजार पूरे किये जा चुके हैं। इसके अलावा भी आवश्यकता के अनुरूप मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जलाभिषेक कार्यक्रम के अंतर्गत जल संरक्षण के काम लगातार जारी हैं। सभी भवनरहित पंचायतों में भवन निर्माण का कार्यक्रम लिया गया है।

9. नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 29 वृहद, 135 मध्यम और तीन हजार लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की योजना बनायी गयी है। नर्मदा घाटी विकास विभाग ने अगले वर्ष 54 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा निर्मित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त सात वृहद, 23 मध्यम एवं 1424 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें से दो मध्यम तथा 261 लघु सिंचाई योजनाएं इसी वर्ष पूर्ण हो जायेंगी।

10. मेरी सरकार द्वारा अल्पावधि कृषि ऋण की वर्तमान 5 प्रतिशत ब्याज दर को और कम किया जायेगा। इस वर्ष किसानों को 3600 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। सहकारी बैंकों द्वारा 34 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। ''सबका सहकार-सबका उद्धार'' योजना के अन्तर्गत 80 हजार सीमांत एवं लघु कृषकों को सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनाया गया है। उचित मूल्य दुकानों में नवीन विक्रेताओं के पद पर महिलाओं की नियुक्ति भी की जायेगी।

11. मेरी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की जैविक कृषि नीति शीघ्र लागू की जायेगी। कृषकों के खेतों की गहरी जुताई के लिए दस हजार हेक्टेयर में 'हलधर योजना' प्रारम्भ की गई है। अगले साल इसका और अधिक विस्तार किया जायेगा। होशंगाबाद जिले के पवारखेड़ा में 170 करोड़ रुपये लागत का कम्पोजिट लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है। जबलपुर के ग्राम खेरी शाहपुरा में आधुनिक सुविधाओं से युक्त फूड पार्क का काम भी शुरू कर दिया गया है। भोपाल के नवीन मण्डी प्रांगण करोंद में आधुनिक होलसेल मार्केट स्थापित किये जाने की परियोजना भी स्वीकृत कर दी गई है।

12. आगामी पांच वर्षों में उद्यानिकी का उत्पादन दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धनिया एवं लहसुन के उत्पादन में प्रदेश अग्रणी है। उद्यानिकी प्रशिक्षण का वृहद कार्यक्रम बनाया गया है। अगले वर्ष गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लघु एवं सीमांत किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को साढ़े तीन लाख सब्जी बीज पैकेट नि:शुल्क वितरित किये जायेंगे।

13. मेरी सरकार द्वारा जबलपुर में प्रदेश के प्रथम पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान सहकारी दुग्ध संघों द्वारा दूध के क्रय मूल्य में औसतन 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है।

14. मेरी सरकार ने 75 हजार 434 मछुआरों का वर्ष 2009-10 में दुर्घटना बीमा कर राष्ट्रीय स्तर का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। मछुआरों को किसानों की भांति क्रेडिट कार्ड दिये जा रहे हैं।

15. शिक्षा मेरी सरकार की प्राथमिकता है। समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार 38094 संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इस वर्ष 594 प्राथमिक शालाओं

का उन्नयन और 729 सैटेलाइट शालाओं की स्वीकृति दी गई। कुल 54 लाख बालिकाओं को नि:शुल्क गणवेश प्रदान किया गया है। पिछले छ: वर्षों में मेरी सरकार ने दस लाख से अधिक बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिलें प्रदान की हैं। पहली से बारहवीं कक्षा तक के बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जा रही हैं। 684 प्राथमिक शाला भवन तथा 18 हजार 493 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण स्वीकृत किया गया है। नि:शक्त बच्चों के लिये 40 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। दृष्टिवाधित विद्यार्थियों के लिये कक्षा एक से आठ तक की पुस्तकें ब्रेल लिपि में भी विकसित की गई हैं। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों का वृहद स्तर पर निर्माण एवं उन्नयन किया जायेगा।

16. सरकार द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का गठन अक्टूबर 2009 में किया गया। पाठ्यक्रमों का सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्निर्धारण किया गया है। इस वर्ष अनुसूचित जाति के 50 हजार और अनुसूचित जनजाति के 33 हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गईं। सेमेस्टर प्रणाली से परीक्षा परिणाम और कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार हुआ है.

17. वर्ष 2009–10 में मध्यप्रदेश में तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थाओं की संख्या 771 से बढ़ाकर 922 की गयी है जिससे प्रवेश क्षमता बढ़कर लगभग एक लाख 41 हजार हो गयी है। इस वर्ष पांच पॉलीटेक्निक महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं और नौ नवीन पॉलीटेकनिक महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। आई.आई.टी., इन्दौर के लिये 432 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। प्रदेश की 36 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उन्नयन किया जा रहा है। धार एवं बैतूल की जिला जेलों में आई.टी.आई. प्रारंभ किये जायेंगे।

18. देश के प्रथम हायब्रिड रोबोटिक्स तारामंडल एवं बैधशाला का निर्माण उज्जैन में किया जा रहा है। हायर सेकेण्डरी की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को देश के किसी भी विश्वविद्यालय, संस्थान, प्रयोगशाला में शोध कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायगी।

19. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना अन्तर्गत प्रदेश में 400 आयुष चिकित्सकों के पद भरे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 300 एलोपैथिक चिकित्सकों की पदस्थापना

की गई है तथा 103 और चिकित्सकों की पदस्थापना की जा रही है। संस्थागत प्रसव वर्ष 2005 में 26 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया है। नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयां 14 जिलों में स्थापित हो चुकी हैं तथा अगले वर्ष तक शेष सभी जिला चिकित्सालयों में स्थापित हो जायेंगी। प्रदेश के विभिन्न शहरों में 108 नंबर की सौ एम्बुलेंस चलाई जायेंगी जिनका आगे विस्तार किया जायेगा। आशा कार्यकर्ताओं की संख्या 46 हजार से बढ़ाकर 71 हजार की जा रही है। प्रदेश के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 9 हजार से बढ़ाकर 13 हजार की गयी है। आदिवासी क्षेत्रों में दीनदयाल चलित अस्पताल सेवा द्वारा 63 लाख से अधिक मरीजों का नि:शुल्क उपचार किया गया।

20. महिलाओं के लिये पंचायतों एवं नगरीय निकायों में प्रथम बार 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ निर्वाचन की कार्यवाही सफलतापूर्वक सम्पन्न की गई है। अब 1 लाख 98 हजार महिला जनप्रतिनिधि अपने दायित्व का निर्वहन करेंगी। महिला सशक्तीकरण के लिये संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक लगभग 3 लाख 96 हजार बालिकाओं को लाभ दिया

जा चुका है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ एक लाख से ज्यादा कन्याओं को मिल चुका है। सांझा चूल्हा व्यवस्था में 65 हजार महिला स्व-सहायता समूह काम कर रहे हैं। लगभग 20,000 नए आंगनवाड़ी एवं उप आंगनवाड़ी केन्द्र शुरू किये जा रहे हैं। गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण पुनर्वास हेतु अनेक केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं। इन सब कोशिशों से प्रदेश में कुपोषण की दर में कमी आई है।

21. प्रदेश में नई औद्योगिक नीति के तहत बड़ी संख्या में निवेश संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। सरकार की उद्योग हितैषी नीति के फलस्वरूप कुल 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाएं स्थापित हो रहीं हैं। प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से प्रथम डायमंड प्रोसेसिंग इकाई बक्स्वाहा जिला छतरपुर में स्थापित हुई है। भारत-ओमान रिफायनरी बीना में क्रूड ऑयल का शोधन शीघ्र ही प्रारंभ हो जायेगा। इसके अलावा 90 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मूर्त रूप देने की कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है। ग्यारह जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का काम प्रगति पर है। बीते पांच वर्षों में 89 वृहद उद्योगों तथा 87 हजार से

अधिक लघु और अति लघु उद्योगों की स्थापना हुई। इससे दो लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इन्दौर में बायो-टेक पार्क निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकसित किया जा रहा है।

22. वर्ष 2008-09 में हीरा, ताम्र अयस्क, डायस्पोर तथा पायरोफिलाइट के उत्पादन में हम देश में प्रथम रहे। प्रदेश में 22 कोयला ब्लाकों के आवंटन की कार्यवाही पूरी हो चुकी है जिससे प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक के निवेश की संभावना निर्मित हुई है।

23. मेरी सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों के समग्र विकास एवं कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक लाख से अधिक दावे मान्य कर 79 हजार से अधिक वन अधिकार पत्र हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं। यह कार्यवाही सतत जारी है। वनवासियों की भूमि के समेकित विकास का काम भी किया जा रहा है। प्रदेश के 50 जिलों में से 49 जिलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय स्वीकृत हो गये हैं। वर्ष 2010-11 में मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिये 20

आश्रम, 20 प्री-मेट्रिक छात्रावास, दो पोस्टमेट्रिक छात्रावास खोले जायेंगे। पूर्व से संचालित छात्रावासों एवं आश्रमों में तीन हजार सीट्स की वृद्धि की जायेगी। आगामी वर्ष में माध्यमिक शालाओं तथा हाईस्कूल के उन्नयन तथा छात्रावास, आश्रम एवं स्कूल भवनों के निर्माण का वृहद कार्य प्रस्तावित है।

24. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय करने की निर्धारित समय-सीमा छह माह से घटाकर एक माह कर दी गयी है। बैकलॉग पदों की पूर्ति के लिये विशेष भरती अभियान की समय-सीमा भी जून 2010 तक बढ़ा दी गयी है। इन वर्गों के अभ्यर्थियों को एयर होस्टेस एवं फ्लाइट स्टीवर्ड का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार, स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। इस वर्ग के लिये सभी जिला मुख्यालयों पर 50 सीटर कन्या छात्रावास भवन तथा सभी संभागीय मुख्यालयों में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2009-10 में पिछड़े वर्ग के 28.75 लाख

विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के 21 हजार छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। मेरी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों ने लाभ उठाया है। सामान्य निर्धन वर्ग के लिये आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, उच्च शिक्षा के लिए ऋण गारंटी की माँ सरस्वती योजना, सांदीपनि संस्कृत भाषा प्रसार योजना, छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति योजना जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं।

25. निर्माण मजदूरों के लिये संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत दस लाख से अधिक मजदूरों का पंजीयन किया गया। लगभग एक लाख मजदूरों को 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता दी गयी। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में दिसम्बर 2009 तक लगभग 14 लाख भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों को पंजीकृत कर उन्हें सहायता देने का काम शुरू कर दिया गया है।

26. मेरी सरकार द्वारा उत्थान अभियान के अन्तर्गत नि:शक्तजनों के परीक्षण, प्रमाण-पत्रों, कृत्रिम अंगों, उपकरणों का वितरण एवं शल्य चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

27. मेरी सरकार द्वारा इस वर्ष भी गेहूं पर सौ रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जायेगा। धान खरीदी पर पचास रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया है। कम्प्यूटरीकृत राशन कार्ड तथा फूड कूपन बनाये जाने की कार्यवाही भी की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिये टोल फ्री राज्य स्तरीय कॉल सेंटर प्रारम्भ किया गया है।

28. मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में विधिक सहायता के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यक्रमों के माध्यम से 1,15,000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने और आठ हजार प्रकरणों में विधिक सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सुलभ न्याय देने की दृष्टि से 40 ग्राम न्यायालय स्थापित किये गये हैं एवं 49 ग्राम न्यायालय और शुरू किये जा रहे हैं।

29. मेरी सरकार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद कुशल प्रबंधन कर राजकोषीय घाटे को वैधानिक सीमा में रखा है।

30. प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को छठवें वेतनमान का लाभ दिया गया और कर्मचारियों को

एरियर्स की राशि का भुगतान पांच समान किश्तों में करने का निर्णय लिया गया है।

31. मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2010 को बांस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत लगभग 5 करोड़ बांस के पौधे रोपित किये जायेंगे। वन अपराध की सूचना देने के लिए भोपाल में राज्य स्तरीय वन अपराध सूचना केन्द्र की स्थापना की गई है। भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत जुर्माने की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वन्य जीवन व्याधि शोध केन्द्र जबलपुर में स्थापित किया जा चुका है।

32. मेरी सरकार द्वारा 'भारत पर्व' एवं 'अपना मध्यप्रदेश' की अवधारणा को मूर्त रूप देने की दृष्टि से कलाकारों एवं साहित्यकारों को व्यापक मंच दिया गया है। संस्कृति एवं भारतीय साहित्य के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिये 'धर्मपाल' शोधपीठ एवं 'महाराजा विक्रमादित्य' शोधपीठ की स्थापना की गई है। प्रदेश के सांस्कृतिक अंचलों के मुख्यालय पर कला संकुल बनाये जा रहे हैं।

33. खेलों को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस वर्ष 25 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 240 राष्ट्रीय पदक जीते हैं। गत वर्ष 11 खिलाड़ियों को विक्रम, 15 एकलव्य, तीन प्रशिक्षकों को विश्वामित्र एवं एक को लाईफ टाईम एचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय हॉकी की मेरी सरकार ने सामयिक मदद की तथा आगे भी उपयुक्त मदद के लिये तैयार है।

34. मेरी सरकार ने धार्मिक, ईको, साहसिक तथा जलाधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया है। पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश प्राप्त करने की लैंड बैंक योजना के उत्साहजनक परिणाम आ रहे हैं। गंतव्य विकास के कार्य निरंतर जारी हैं। प्रदेश के प्रमुख जलाशयों में निजी निवेश के माध्यम से पर्यटन सुविधाएं विकसित करने की नीति लागू की गई।

35. मेरी सरकार आम लोगों से जुड़ी सरकार है। विभिन्न वर्गों की समस्याओं के समाधान और उनके विकास के लिए राज्य स्तरीय पंचायतें आयोजित कर योजनाएं बनायी गयीं। हर मंगलवार को शासकीय कार्यालय स्तर पर आयोजित 'जनसुनवाई कार्यक्रम' के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है।

36. मेरी सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता, सुचिता और कसावट के लिए कई कदम उठाए हैं। सभी कार्य विभागों में ई-टेन्डरिंग की व्यवस्था लागू की गई है। परख, समाधान एक दिवस, समाधान ऑनलाइन जैसे नवाचार इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित हैं। मेरी सरकार की पहली राज्य सरकार है जिसने शासकीय सेवकों के संपत्ति विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है।

37. मेरी सरकार ने सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को उच्च प्राथमिकता दी है। प्रदेश में लगभग सात हजार केन्द्रों से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा वन विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई-गवर्नेंस का गोल्डन आइकॉन और ग्रामीण विकास विभाग को सिल्वर आइकॉन पुरस्कार प्राप्त हुआ। दक्षिण एशियाई देशों के लिये स्थापित प्रतिष्ठित 'मंथन पुरस्कारों' से स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि तथा वन विभाग को पुरस्कृत किया गया। कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ ई गवर्न्ड स्टेट का पुरस्कार दिया गया। ये सभी पुरस्कार मेरी सरकार द्वारा किये जा रहे श्रेष्ठ कार्यों का प्रमाण हैं।

38. मेरी सरकार बाहुबलियों के विरुद्ध कार्यवाही कर कानून के राज की स्थापना करने में सफल रही है। खनिज माफिया, कालाबाजारी, जमाखोरी, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार तथा भू-माफिया पर प्रभावी नियंत्रण किया है। मेरी सरकार द्वारा चलाये गये दस्यु उन्मूलन अभियान सफल रहे। इसी प्रकार नक्सली समस्या पर भी काबू पाया गया है। सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भावना का सुस्थिर वातावरण बना है। गृह निर्माण सहकारी समितियों की अवैध गतिविधियों के प्रति कठोर कार्यवाही कर उनके वास्तविक सदस्यों को हक दिलाया जा रहा है। पुलिस को दक्ष बनाने के लिये आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं तथा उनके प्रशिक्षण पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस बल में पन्द्रह सौ नये पदों का निर्माण किया गया है। होमगार्ड के मानवेतन तथा भोजन राशि में भी वृद्धि की गई है। प्रदेश में विभिन्न तरह के चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए हैं।

आइये, हम सब मिलकर अपना मध्यप्रदेश बनायें।

जय हिन्द।